स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

स्वच्छता समाचार

खंड 2 I अंक 8 I मई 2023

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण न्यूज़लेटर

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

"'SDG 6.2 को प्राप्त करने की हमारी यात्रा में, 2014 से, हमने 105 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है और 600 मिलियन से अधिक भारतीयों के बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से स्वच्छता की आदतों को बदल दिया है। यह अभियान भारत के सभी 600 हजार गांवों और समुदायों में स्थायी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन समाधान सुनिश्चित करने से संबंधित हमारे प्रयासों के माध्यम से जारी है।"

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, 24 मार्च, 2023

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

28 अप्रैल, 2023 तक

ODF+

ODF- भारत के 2,80,822 से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उदीयमान: **1,96,869**
- उज्ज्वल: **29,871**
- उत्कृष्ट: **54,082**

1,55,564 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।
2,27,779 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।
4,66,102 गांवों में कम से कम गंदगी है।
4,55,618 गांवों में कम से कम पानी जमा है।
देश भर में **562** पूर्ण गोबरधन संयंत्र हैं।
794 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की गई है।

रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान: अभियान के तहत, 4,73,763 को रेट्रोफिट किया गया जिनमें **2,93,842** से एकल गड्ढे वाले शौचालयों को ट्विन पिट शौचालयों में बदल दिया गया है और से **1,79,921** सैप्टिक टैंक शौचालयों को एयर वेंट्स और सोख्ता गड्ढों से जोड़ा गया है।

क्षमता निर्माण
- **8,039** एसबीएम-जी चरण II में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए
- **4,31,723** व्यक्तियों को ODF Plus के सभी कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया

स्वच्छता पखवाड़ा

विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा 1-15 अप्रैल 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान, सफाई संबंधी विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें शपथ ग्रहण समारोह, वृक्षारोपण, सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले बैनरों का प्रदर्शन और पूरे कार्यालय परिसर की सफाई शामिल थी। न्याय विभाग के कर्मचारियों ने 8 अप्रैल 2023 को जैसलमेर हाउस में श्रमदान में भाग लिया।

अप्रैल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने वाले अन्य मंत्रालय थे: संस्कृति मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय (15-30 अप्रैल तक)।

केरल ने समुद्र तट सफाई अभियान के साथ शून्य कचरा दिवस मनाया

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

सुचित्व मिशन जो आईटी फर्म यूएसटी के सहयोग से केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) के तहत कचरा प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) है; केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में चिरायिनकीझू ग्राम पंचायत; और हरित कर्मसेना या ग्रीन टास्क फोर्स ने 30 मार्च, 2023 को समुद्र तट सफाई अभियान के साथ अपना पहला शून्य कचरा दिवस मनाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता चिरायिनकीझू ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, श्री पी. मुरली, और सुचित्व मिशन के कार्यकारी निदेशक श्री के. टी. बालाभास्करन ने की। उन्होंने शून्य कचरा दिवस का संदेश दिया। केरल सरकार के एलएसजीडी और आबकारी मंत्री श्री एम. बी. राजेश ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कचरे को कम करने और स्वच्छतर पर्यावरण की दिशा में कदम उठाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सफाई कार्य के दौरान, पेरूमाथुरा समुद्र तट, जो इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, के किनारों को अच्छी तरह से साफ किया गया था।

संपर्क: akhilesh@washinstitute.org

पतोरा एफएसटीपी ओ एंड एम के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा गया

छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की पतोरा ग्राम पंचायत में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) को आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 2023 को स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों, एसबीएम-जी और जिला परिषद के अधिकारियों, पीआरआई, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। अब से ग्राम पंचायत FSTP के संचालन और रखरखाव का ध्यान रखेगी।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

वर्ष 2020 में स्थापित एफएसटीपी के लिए हैंडओवर संबंधी दस्तावेज पर पतोरा की सरपंच, श्रीमती अंजिता गोपेश साहू और श्री मानस कुमार बिस्वाल, राज्य कार्यक्रम निदेशक - जल सहायता द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

जबकि ग्राम पंचायत FSTP के ओएंडएम संबंधी खर्चों का ध्यान रखेगी, जिला एसबीएम-जी ने समझौता ज्ञापन के अनुसार संयंत्र के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहायता का वचन दिया है। वाटरएड, प्रयोगशाला परीक्षण और अन्य तकनीकी जानकारी के माध्यम से सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। पिछले 3 वर्षों में, विकास भागीदार, संचालन लागत को पूरा करने, ट्रक लोड संबंधी एक डेटाबेस बनाने और नियमित मरम्मत के कार्य में शामिल रहा है। इसने खाद बनाने और बेचने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत का सहयोग भी किया है। इस बीच, आईसीआईसीआई फाउंडेशन (सीएसआर पार्टनर) ने ग्राम पंचायत को डीस्लजिंग के लिए एक वाहन प्रदान किया।

अब यह ग्राम पंचायत पतोरा और आसपास के अन्य गांवों में डीस्लजिंग संबंधी गतिविधियां उपलब्ध कराकर राजस्व अर्जित करने में सक्षम होगी।

संपर्क: purubabu.rb@gmail.com

आरआरसी, खांगचेन्दोंगा के जंगलों को साफ-सुथरा और कूड़े से मुक्त रखता है

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

जैसा कि देश के अन्य भागों में किया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिक्किम जिले के युकसोम शहर में एक संसाधन वसूली केंद्र (RRC) स्थापित किया गया है। इस सुविधा में, कचरे को प्राप्त किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उसकी छंटाई की जाती है, संग्रहीत किया जाता है, और उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए संसाधित किया जाता है, जिससे अंततः लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे को कम किया जाता है। यह, यह सुनिश्चित करने के लिए काफी उपयोगी है कि खानचेन्दोंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल कूड़े और प्लास्टिक कचरे से मुक्त हों।

युकसोम, गोएचला ट्रेक का शुरूआती स्थान है, यह ट्रेक देश के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्गों में से एक है। प्रत्येक वसंत ऋतु में इस शहर में अनेक पर्यटक दिखाई देते हैं जो सुहावने मौसम का आनंद लेने और ट्रेक में भाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से कचरा प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

फिर भी, सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग द्वारा स्थापित आरआरसी के कारण युकसोम के पर्यटन स्थल अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ हैं। यह विभाग जंगलों के रखरखाव में अभूतपूर्व काम कर रहा है।

हावड़ा में SHG सदस्यों को ठोस कचरा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया

जैविक और अजैविक कचरे दोनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, पश्चिम बंगाल में हावड़ा के जिला प्रशासन ने 14 से 15 मार्च 2023 तक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) चरण-II का एक अनिवार्य घटक है। इसमें पर्यावरण की रक्षा करने और सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का उचित प्रबंधन शामिल है। जबकि बायोडिग्रेडेबल कचरे में रसोई का कचरा, कृषिजनित अपशिष्ट और मानव तथा पशुजनित ऐसा कचरा शामिल हैं, जिन्हें जीवित सूक्ष्मजीवों की जैविक कार्रवाई से विघटित किया जा सकता है; गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे में प्लास्टिक, धातु, कांच आदि शामिल हैं, जिन्हें जैविक रूप से विघटित नहीं किया जा सकता है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संकरैल ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन सचिव-जिला परिषद, स्वच्छता प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक, प्रधान-ग्राम पंचायत, संयुक्त खंड विकास अधिकारी, संसद सदस्यों, स्वच्छता कर्मचारियों और एसएचजी सदस्यों सहित लगभग 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

स्रोत पर पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, बायोडिग्रेडेबल कचरे की खाद बनाने, गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को पुनर्नवीनीकरण और गैर-पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट में अलग करने और फॉरवर्ड लिंकेज से ठोस कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।

संपर्क: howrahmnb2018@gmail.com

गांधीनगर में G-20 की बैठक में SBM-G का प्रतिनिधित्व

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

गांधीनगर, गुजरात के महात्मा मंदिर में आयोजित पर्यावरण और जलवायु स्थिरता संबंधी कार्य समूह (ECSWG) की दूसरी बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण भारत को स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है।

27-29 मार्च, 2023 के दौरान आयोजित बैठक में 19 जी 20 सदस्य देशों, 09 आमंत्रित देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्री विकास शील ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के संबंध में एक प्रस्तुति दी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भारत सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सत्र के बाद प्रतिनिधियों ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत संगठनों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टालों का दौरा किया, जिसमें विभिन्न विषयों को प्रदर्शित किया गया और अटल जल, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान, राष्ट्र जल मिशन आदि में गुणवत्तापूर्ण कार्य साझा किए गए।

NSSC ने 52,049 करोड़ रुपये के SBM-G बजट को मंजूरी दी

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (ALP) पर विचार करने के लिए 28 मार्च, 2023 को हुई राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (NSSC) की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अभिसरण के माध्यम से SBM-G चरण II गतिविधियों के लिए 52,049 करोड़ रुपये के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट को मंजूरी दी गई है। राज्यों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय हिस्से की निधियों में 14,030 करोड़ रुपये के अनंतिम आवंटन के बारे में सूचित किया गया है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

राज्यों के कार्यनिष्पादन की सराहना करते हुए श्रीमती विनी महाजन, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 03 संघ राज्य क्षेत्र न केवल खुले में शौच मुक्त हैं, बल्कि उनके सभी गांव भी ODF Plus उत्कृष्ट की श्रेणी में हैं।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य थे 100% ODF Plus गांवों के साथ तेलंगाना, इसके बाद 95.7% ODF Plus गांवों के साथ तमिलनाडु और 93.7% ODF Plus गांवों के साथ कर्नाटक का स्थान था।

दूसरी ओर, उल्लेखनीय प्रगति करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश जो वर्ष 2022 में 18% ODF Plus गांवों से वर्ष 2023 में 79% गांवों तक पहुंच गया; इसके बाद मध्य प्रदेश जो वर्ष 2022 में 6% ODF Plus गांवों से वर्ष 2023 में 62% गांवों में पहुंच गया; और उत्तर प्रदेश जो वर्ष 2022 में 2% ODF Plus गांवों से वर्ष 2023 में 47% गांवों तक पहुंच गया। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, मिजोरम वर्ष 2022 में 6% ODF Plus गांवों से वर्ष 2023 में 35% गांवों तक पहुंच गया। राज्यों द्वारा किए गए कुल खर्च के संबंध में मंत्री महोदय ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में उच्च निधि व्यय (90 प्रतिशत से अधिक) के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की।

स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा के संबंध में ToT

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G) के चरण 2 के तहत, संपूर्ण स्वच्छता की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्वच्छता कर्मचारी शायद इस पूरे प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में से एक है और उसे अधिक ध्यान और सहयोग की आवश्यकता है। रूरल वाश पार्टनर्स फोरम (RWPF) कार्य आवंटन के तहत यूनिसेफ को क्षमता निर्माण संबंधी काम सौंपा गया है। उसी के अनुरूप, वर्ष 2023 में, यूनिसेफ ने ग्रामीण स्वच्छता कर्मचारियों की क्षमताओं और कार्य वातावरण को मजबूत करने की दिशा में कार्य शुरू किया।

अभियान के उद्देश्य:

- कार्य की भूमिकाओं के अनुसार स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक खतरों के साथ बेहतर समझ और सहानुभूति
- सफाई कर्मचारियों के काम के माहौल में सुधार करना
- स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देना
- स्वच्छता कर्मचारियों को तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में जानकारी प्रदान करना
- स्वच्छता कर्मचारियों को तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक बनाना
- स्वच्छता कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाना - संविदात्मक तौर-तरीके - स्वच्छता क्षेत्र को व्यावसायिक बनाना
- समुदाय में स्वच्छता कार्यकर्ता की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संचार अभियान चलाना

यूनिसेफ इंडिया और शहरी प्रबंधन केंद्र (UMC) के बीच एक संयुक्त पहल के तहत, 'ग्रामीण स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके काम के माहौल में सुधार करने' के लिए एक विस्तृत टूलकिट विकसित किया गया है। इसे 4-7 अप्रैल 2023 तक अहमदाबाद में 16 राज्यों के 51 राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रसारित किया गया था। क्षेत्र की वास्तविकता को समझने और आपसी अनुभव से सीखने के लिए, प्रतिभागियों ने अहमदाबाद, गुजरात के तीन गांवों का भी दौरा किया। टूलकिट सुझावपरक है और इसे राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और संदर्भित किया जा सकता है।

तैयारी: भागीदारी के तहत तैयार आईईसी सामग्री के साथ मॉड्यूल का एक फील्ड-परीक्षण फरवरी और मार्च 2023 में 2 पायलट राज्यों (बिहार और गुजरात) में किया गया। इन पायलटों से प्रतिक्रिया को अंतिम टूलकिट में एकीकृत किया गया, जिसे प्रतिभागियों को प्रसारित किया गया। इस टूलकिट में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा से संबंधित एक मॉड्यूल; सफाई कर्मचारियों के लिए एक पुस्तिका; और आईईसी सामग्री (4 पोस्टर, 5 GIFS, और 1 लघु फिल्म) शामिल है।

यह अभियान वर्ष 2023 में 16 राज्यों - असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 2000 मास्टर ट्रेनर बनाने और 16000 स्वच्छता कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए चलाया जाएगा।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग और स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों और पात्रताओं के संबंध में संवेदनशीलता इन प्रशिक्षणों के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर भी स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए संबंधों का समर्थन करेंगे और उन्हें मजबूत करेंगे।

स्वच्छता जंबल

निम्नलिखित जंबल को व्यवस्थित क्रम में लगाकर नीचे दिए गए प्रत्येक खाने में एक अक्षर का प्रयोग करके स्वच्छता कर्मचारियों और उनके काम से संबंधित एक शब्द बनाएं।

YNGIDTI □□□□□□□

PEP □□□

Y T FSAE □□□□□□

R ADZH A □□□□□□

LOVESG □□□□□□

अब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए वृत्ताकार अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए: स्वच्छता कर्मचारी क्या हैं।

स्वच्छता

□□□□□□

Answers: Dignity, PPE, Safety, Hazard, Gloves, HEROES

बारामूला में पिंक सोसाइटियों द्वारा समग्र विकास को बढ़ावा देना

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

जम्मू-कश्मीर के बारामूला के जिला प्रशासन ने पिंक सोसाइटियों का गठन किया है। प्रत्येक सोसाइटी में जिले के 217 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के 2-3 शिक्षक और 4-6 छात्राएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाना और किशोर लड़कियों का सहयोग करना, उनके समग्र विकास को सुविधाजनक बनाना और उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए तैयार करना है। बारामूला के जिला विकास आयुक्त की इस पहल का व्यापक उद्देश्य लक्षणों और प्रजनन पथ के संक्रमण को रोकने के तरीकों, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों और साधनों, किशोरावस्था के दौरान गर्भधारण के दुष्परिणाम और इससे बचने के तरीकों और सेवाओं के बारे में जागरूकता विकसित करना था जिन्हें किशोरियां सकारात्मक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए प्राप्त कर सकती हैं।

संस्थानों में पिंक सोसाइटियां छात्रों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं को साझा करने और शर्म या अपराधबोध के बिना सेवाओं तक पहुंचने में सहज महसूस कराती हैं। छात्रों और शिक्षकों की समान प्रारंभिक प्रतिक्रिया को देखते हुए, पिंक सोसाइटियों की भूमिका को महत्व मिला है, जिससे वे स्वच्छता, सफाई, गरिमा और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने के संबंध में उन संस्थानों का एक अभिन्न अंग बन गई हैं।

drsjk47@gmail.com

राज्य की एक आवाज

शौचालय क्लिनिक: शौचालय से संबंधित सभी कठिनाइयों के लिए वन-स्टॉप समाधान

श्री राहुल कुमार
मिशन निदेशक, एसबीएम (जी), बिहार

टॉयलेट क्लिनिक पहल को 'वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर' के रूप में शुरू किया गया था ताकि शौचालयों की रेट्रोफिटिंग, संचालन, रखरखाव और सफाई से संबंधित सभी समस्याओं का कम लागत पर निराकरण किया जा सके। यह एक अभिनव समुदाय-आधारित कार्रवाई है, जिसकी स्थापना ब्लॉक स्तर पर की गई है।

इसके तहत एक ही छत के नीचे रेट्रोफिटिंग सामग्री, हाईटेक सफाई उपकरण, प्रशिक्षित राजमिस्त्री और स्वच्छता चौकीदार उपलब्ध हैं। रेट्रोफिटिंग सेवाओं और सामग्रियों जैसे बालू, सीमेंट, पैन, पाइप आदि के लिए दरें तय की जाती हैं। शौचालय क्लिनिक को कॉल करके या उससे जुड़े स्वच्छता चौकीदार/राजमिस्त्री से संपर्क करके कोई भी इस सेवा का लाभ उठा सकता है। आवश्यक रेट्रोफिटिंग सामग्री को दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा और परिवारों से केवल उपभोग की जाने वाली सामग्री के लिए विशिष्ट सेवा शुल्क के साथ शुल्क लिया जाता है।

शौचालय क्लीनिक व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की मरम्मत, संचालन और रखरखाव में उपयोगी साबित हो रहे हैं। अब तक मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, गया, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में सात शौचालय क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इन्हें यूनिसेफ के सहयोग से बिजनेस मॉडल के तौर पर चलाया जा रहा है।

राज्य के दौरे

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) और जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में एक बैठक की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।

इस बैठक में डीडीडब्ल्यूएस की सचिव श्रीमती विनी महाजन; श्री विकास शील, अपर सचिव और मिशन निदेशक-जेजेएम; और श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक-एसबीएम-जी भी उपस्थित थे। केरल सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव, केरल; जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव; अपर मुख्य सचिव - स्थानीय स्व-शासन विभाग (LSGD), और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। बैठक में केरल के जल संसाधन मंत्री श्री रोशी ऑगस्टीन और केरल के स्थानीय स्व-शासन विभाग के मंत्री श्री एम. बी. राजेश भी उपस्थित थे।

श्रीमती विनी महाजन सचिव - डीडीडब्ल्यूएस

5 अप्रैल: सचिव-डीडीडब्ल्यूएस और कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती वंदिता शर्मा ने विधान सौध, बेंगलुरु में SBM-G और जेजेएम की प्रगति के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।
इस बैठक में श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक-एसबीएम-जी; श्री रमन्ना रेड्डी, एसीएस एवं विकास आयुक्त, कर्नाटक सरकार (GoK); डॉ अजय नागभूषण एमएन, सचिव यूडीडी जीओके; एसीएस ग्रामीण विकास और पंचायती राज (GoK); प्रोफेसर गोपाल नाइक - आईआईएम बैंगलौर; और कर्नाटक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

11 अप्रैल: श्रीमती विनी महाजन, सचिव-डीडीडब्ल्यूएस और श्री इराई अन्बू, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार ने SBM-G और जेजेएम की प्रगति के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस बैठक में SBM-G के संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव और श्री शिव दास मीणा एसीएस, सुश्री अमुधा, प्रधान सचिव SBM-G; डॉ. दारेज़ अहमद, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; श्री प्रशांत एम. एस., मिशन निदेशक, SBM-G और तमिलनाडु के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

18 अप्रैल: डीडीडब्ल्यूएस की सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आर्यनाड में गोबर-धन परियोजना, **वट्टापाडा** में एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर और कन्याकुलंगरा एयरोबिन साइट का दौरा किया। उन्होंने मणिकल के पंचायत हॉल में राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा की, जहां हरित मित्र ऐप, जो कचरा प्रबंधन का एक डिजिटल समाधान है, के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। यह ऐप हरित कर्म सेना की गतिविधियों और इसके कचरा प्रबंधन कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्मार्ट कचरा निगरानी प्रणाली है।

इसके बाद, सचिव-डीडीडब्ल्यूएस ने 19 अप्रैल को SBM-G और JJM की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में SBM-G के संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव; श्री शिव दास मीणा एसीएस, सुश्री अमुधा, प्रधान सचिव SBM-G; डॉ. दारेज़ अहमद, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; श्री प्रशांत एम. एस., मिशन निदेशक SBM-G और तमिलनाडु के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केरल के दौरे में ODF Plus उपलब्धियों, विशेष रूप से ग्रामीण केरल में सीएससी, जीओबीएआरधन संयंत्र, एयरोबिन, आरआरएफ और एमसीएफ, का आकलन करने के लिए ग्राम पंचायत के क्षेत्र संबंधी दौरे शामिल थे,

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक

तमिलनाडु: डीडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G) श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु का दौरा किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राम स्वच्छता परिपूर्णता योजना (VSSP) पर चर्चा के बाद, उन्होंने माम्बक्कम, मणिवक्कम और वेल्लापुथुर ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां उन्होंने रूटज़ोन टेक्नोलॉजी, एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर, एक माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर, एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई और एक ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा का उपयोग करके ग्रेवाटर प्रबंधन संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया।

केरल: संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने पूलंथरा में रिसोर्स रिकवरी सुविधा; कनियापुरम में सामुदायिक स्वच्छता परिसर; कनियापुरम में सामग्री संग्रहण सुविधा; वलियाकाडा में सामुदायिक कंपोस्टिंग सिस्टम और वलियाकाडा बाजार में सीएससी; चिरायिनकीझू में सीएससी का दौरा किया और चिरायिनकीझू में पंचायत कार्यालय में चर्चा की, जहां हरिता मित्र ऐप की प्रस्तुति दी गई।

सचिव की कलम से

दिनांक 28 मार्च, 2023 को गांधीनगर में आयोजित पर्यावरण और जलवायु स्थिरता संबंधी कार्य समूह की दूसरी बैठक के दौरान SDG 6.2 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उपलब्धियों और भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। G-20 प्रतिनिधिमंडल ने देश के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की।

तथापि, पूरे देश को ODF Plus बनाने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास केवल दो साल बचे हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सभी बाधाओं को दूर करें और स्वच्छ तथा हरित भारत के लिए ODF Plus परिसंपत्तियों के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों को अमल में लाएं।

श्रीमती विनी महाजन
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय

मिशन निदेशक की कलम से

राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (NSSC) ने वित्त वर्ष 2023-24 के अभिसरण के माध्यम से SBM-G चरण II गतिविधियों के लिए 52,049 करोड़ रुपये के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट को मंजूरी दी है। ज्ञान से संपन्न, राज्य अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बदलाव लाने के लिए कार्य करते हुए अपने-अपने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गति में तेजी लाने और हर गांव को ODF Plus बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस बीच, रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है, जो डीडीडब्ल्यूएस एमआईएस के अनुसार, यह दर्शाता है कि 4 लाख से अधिक शौचालयों को रेट्रोफिट किया गया है।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, प्रत्येक महीने की 15 तारीख से पहले **swachhbharat@gov.in** अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in